

बिहार एसआईआर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, आधार को 12वां दस्तावेज माना जाएगा

नई दिल्ली, 08 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश दिया कि वह चुनावी राज्य विहार में विशेष गहन पुनरुक्षण (एसआईआर) अधियान के तहत मतदाता पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड को 12वें निर्धारित दस्तावेज के रूप में माने। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि आधार कार्ड स्वीकार किया जाएगा... संस्कृत के प्रामाण के रूप में काम नहीं करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की दो सदस्यीय पीटे ने मामले को अगले सोमवार के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि चुनाव आयोग जमा

किए गए आधार कार्डों की प्रामाणिकता की जांच कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे जाली नहीं हैं। पीटे ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी नहीं चाहता कि चुनाव आयोग अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करे।

बार एंड बैंच की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा कि आधार कार्ड स्वीकार किया जाएगा... संस्कृत मतदाता सूची में शामिल करने या बाहर करने की स्वीकृति के उद्देश्य से... आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज माना जाएगा। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकारी आधार कार्ड की प्रामाणिकता और



वास्तविकता को सत्यापित करने के हकदार होंगे और आधार नामिकता का प्रामाण नहीं होगा... चुनाव आयोग दिन के दौरान निर्देश जारी करेगा। सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने मतदाताओं से आधार कार्ड

दाखिल करने से नहीं रोका है।

उन्होंने अदालत से कहा कि हम पता लगाएँ कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा है। इससे पहले, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि मसौदा मतदाता सूची में दावे, अपतियां और सुधार 1 सितंबर के बाद भी दावर किए ज सकते हैं, लेकिन मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही इन पर विचार किया जाएगा। आयोग ने कहा था कि मसौदा मतदाता सूची में दावे और अपतियां प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक दावर की ज सकती हैं।

निर्वाचन आयोग वोट चोरी के लिए भाजपा का बैक-ऑफिस बन गया है : खरगे

नई दिल्ली, 08 सितम्बर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि यह (आयोग) वोट चोरी के लिए भाजपा का बैक-ऑफिस बन गया है।

खरगे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कालक्रम को समझें। मई 2023 के कर्नाटक चुनाव से पहले, कांग्रेस ने अलंदं निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने का खुलासा किया था। प्रपत्र संख्या-सात में फजीर्वाड़ा कर हजारों मतदाताओं के मताधिकार छीन लिये गये।

उन्होंने कहा, फरवरी 2023 में एक मामला दर्ज किया गया। जांच में 5,994 जाली आवेदनों का खुलासा हुआ। यह मतदाता



धोखाधड़ी के बड़े पैमाने पर प्रयास का एक स्पष्ट प्रमाण है। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने दोषियों को पकड़ने के बाद ही सीआईडी जांच को पटरी से उतार रहा है। खरगे ने कहा, लेकिन यहां है? यह किसे बचा रहा है? यह किसे विभाग को? किसे निर्वाचन आयोग को? किसे आधिकारिक दावों से उतार रहा है।

उन्होंने पूछा, निर्वाचन आयोग ने अचानक महत्वपूर्ण सबूतों को क्यों रोक दिया है? यह किसे बचा रहा है? यह किसे विभाग को? किसे निर्वाचन आयोग को? भाजपा के दबाव में सीआईडी जांच को पटरी से उतार रहा है। लोकतंत्रिक अधिकारों के महत्व को देहराते हुए खरगे ने कहा, हर व्यक्ति के मतदान के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। भारतीय लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए।

सपा शासनकाल में हुई कई सरकारी भर्तियों को जांच के लिए सीबीआई को सौंपा : आदित्यनाथ



लखनऊ, 08 सितम्बर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी (सपा) की विश्विल के दौरान हुई सरकारी भर्तियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि गड़बड़ीयों की वजह से उनकी सरकार ने बहुत सारी भर्तियों की जांच के नियमों अनुरूप ब्यरो (सीबीआई) को सौंप दी थी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधिनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 1112 कनिष्ठ सहायक और 22 एक्सरे तकनीशियन के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यालय को सम्मोहित करते हुए राज्य की पूर्ववर्ती सपा सरकार पर भर्तियों में धांधली किये जाने का आरोप लगाया और

• सुरक्षा तैयारियों का पुलिस आयुक्त ने लिया जायजा।

• मारीशस और भारत के पीएम की अभेद होगी सुरक्षा व्यवस्था

• सुरक्षा गांधी वाराणसी। काशी, जो सदियों से भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रही है, अब एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय नेताओं के दौरे के बाकी की जीवन जेल में ही बिताने पर मजबूर होंगे। उन्होंने कहा, ऐसा इसलिये किलों में छह अलग-अलग लोगों द्वारा नीकरी किये जाने के एक अप्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा, ऐसा इसलिये जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के पथ पर ले जाने के बजाय उससे लगातार दूर ही रखा। प्रशासन ने इस

कहा, किस प्रकार की भर्तियों की होती थीं। हमें बहुत सारी भर्तियों की जांच उस समय सीबीआई को देनी पड़ी थी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 2016 से एक व्यक्ति के नियुक्ति पत्र पर कई अब वे बाकी को जीवन जेल में ही बिताने पर मजबूर होंगे। उन्होंने कहा, ऐसा इसलिये जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के पथ पर ले जाने के बजाय उससे लगातार दूर ही रखा।

दौरे को लेकर सुरक्षा, यातायात और स्वागत व्यवस्थाओं में विशेष तैयारी की है। पुलिस लाइन से ताज होटल तक बनाए गए छह स्वागत पॉइंट इस बात का प्रतीक है कि काशी में आने वाले मेहमानों का सम्मान केवल औपचारिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक भावानाओं से जुड़ा हुआ है। फूलों की पंखुड़ियों और स्थानीय स्वागत परंपराओं के माध्यम से न केवल नेताओं का स्वागत होगा, बल्कि यह काशी की सांस्कृतिक संपन्नता और आतिथ्य भावना का जीवंत चित्र प्रस्तुत करेगा।

राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से ये दौरे महत्वपूर्ण हैं। मारीशस पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता, क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने का अवसर है। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी का शॉर्ट लेकिन प्रभावशाली दौरा भारत की अंतरराष्ट्रीय और आंतरिक कूटनीति को संसुलित रूप से संचालित करने का संदेश देता है। काशी की यह दौरा यह भी है कि वह शहर के देश से लिए गए काशी के नामांकन की अवधारणा है। यह दौरा काशी के दक्षता और शहर की सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन क्षमता का परीक्षण भी है। यह दौरा काशी के धरती पर जब देश और विदेश के नवाया संसेश देना है।

शहर की सांस्कृतिक धरोहर, अतिथि सत्कार और आधुनिक प्रशासनिक काशी की वास्तव में है। यह दौरा काशी के धरती पर जब देश और अवसर को एक विशेष तैयारियां: पुलिस लाइन से ताज होटल तक छह स्वागत पॉइंट बनाए गए हैं।

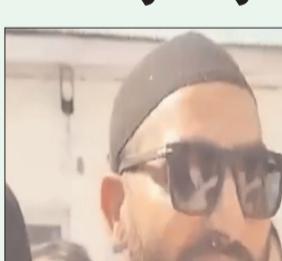
सूलों की पंखुड़ियों और स्थानीय परंपराओं के माध्यम से स्वागत। प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और अतिथि सुविधा को संगम दुनिया की नगरी है कृजहां परपरा और आधुनिकता का संगम दुनिया की नवाया संसेश देना है।

नेता एक साथ बैठेंगे तो यह केवल कूटनीतिक संवाद नहीं होगा, बल्कि गंगा-धारों से उत्तीर्ण सांस्कृतिक ध्वनि का प्रसार होगा जो विश्व को भारत से जोड़ती है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह इस अवसर को ऐतिहासिक बनाए और अनेक लोकतंत्रिक अधिकारों के महत्व को देहराते हुए खरगे ने कहा, हर व्यक्ति के मतदान के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। भारतीय लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए।

विशेष तैयारियां: पुलिस लाइन से ताज होटल तक छह स्वागत पॉइंट बनाए गए हैं।

सूलों की पंखुड़ियों और स्थानीय परंपराओं के माध्यम से स्वागत। प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और अतिथि सुविधा की धरती पर जब देश और विदेश के लिए विशेष प्रबंध किए।

जम्मू-कश्मीर में आप को झटका, विवादों में रहे विधायक मेहराज मलिक पीएसए में गिरफ्तार



जम्मू-कश्मीर के आप आदामी पार्टी (आप) प्रमुख और विधायक मेहराज मलिक को लोडा जिले में सार्वजनिक व्यवस्था को कथित रूप से बिगड़ाने के आरोप में कड़े जन सुनवाई के दो साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी गई। अधिकारियों ने बताया कि विवादों के लिए आप विधायक पार्टी के शेर हैं। वो हमेशा जनता की आवाज बनकर हक की लाइट लड़ते हुए रह रहे। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा उनके खिलाफ एक डॉजियर तैयार करने के बाद, बाद में डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह के आदेश पर उन्हें पीएसए के तहत भद्रवाह जिला जेल में रखा गया। अपने देखा होगा कि एक व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाए।

वहीं, आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि क्या अपने क्षेत्र की जनता के लिए अस्पताल माँगना इतना बड़ा गुनाह है

आखिरी कतार में बैठ कर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया कार्यकर्ताओं को सन्देश

**प्रकृति की नाराजगी को नहीं
समझा तो मानव अस्तित्व खतरे में**



लेती है। आज

के अनियंत्रित बदलाव के दृश्य दिखाई दे रह हैं, वे केवल प्राकृतिक आपदा नहीं हैं, बल्कि हमारी गलतियों का सीधा परिणाम हैं। प्रकृति के इस रौद्र रूप के पीछे महज संयोग या हृकुदरत की नाराजगी हूँ को जिम्मेदार ठहराना पर्याप्त नहीं है। यह आपदाएं सीधे-सीधे जलवायु परिवर्तन, वनों की अंथाधुंध कटाई और अनियंत्रित विकास मॉडल का परिणाम हैं। पहाड़ों का परिस्थितिकी तंत्र अत्यंत संवेदनशील होता है, लेकिन नीतिनिर्माताओं ने पहाड़ों के विकास को मैदानी मॉडल पर ढालने की कोशिश की। बड़े-बड़े होटल, अव्यवस्थित सड़कें, बांध, खनन और निर्माण ने पहाड़ों की नाजुक संरचना को हिला दिया। जब जंगल काटे जाते हैं तो वर्षा का पानी भूमि में समाने के बजाय सीधे तेज धाराओं के रूप में बहने लगता है। यही बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कारण बनता है, इसी से भारी तबाही का मजर देखने को मिल रहा है, देश के बड़े हिस्से में जन-जीवन अस्त-व्यस्त है, लाखों हेक्टर फसलें जनमग्न हैं, जान-माल का नुकसान भी बड़ा हुआ है, भारी आर्थिक नुकसान ने घना अंधेरा बिखर दिया है। चारों ओर चिन्ताओं एवं परेशानियों के बादल मंडरा रहे हैं।

आज की बाढ़ और जल प्रलय केवल पानी का उफान नहीं, बल्कि हमारी गलतियों का आईना है। यह प्रकृति का प्रतिशोध है, उसकी जिम्मेदारी से भी अस्त-व्यस्त होने वाली जलवायु का

की हाल ही में एक और मिसाल सांसदों को मतदान प्रक्रिया की बारीकियां समझाई गईं, ताकि कोई आज भाजपा की कार्यशाला में एक साधारण सांसद की तरह शामिल हुए और कार्यक्रम की कार्यवाही में शुरूआत से ही हिस्सा लिया। यह कार्यशाला उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी के लिए भाजपा सांसदों के लिए आयोजित की गई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी आगे की सीट पर न बैठकर सबसे पिछली पक्की में बैठे और एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह बैठक में भाग लिया इस दौरान सांसदों ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री मोदी को ऐतिहासिक #GenNextGST रिफॉर्म्स के लिए बधाई दी गई। यह रिफॉर्म्स जीएसटी प्रणाली में नई पीढ़ी के सुधारों का हिस्सा हैं, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लाए गए हैं। सांसदों ने प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता की सराहना की और कहा कि इन सुधारों से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान में नहीं पहुंचे, उन्होंने पूरा दिन बिताया। एक आम सांसद की तरह भागीदारी थी। यह तस्वीर देखते ही देखते बायरल हो गई। तब से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में भाजपा की सांसद कार्यशाला के बारे में जिज्ञासा है। लोग सोशल मीडिया में सच्च कर रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं, इस कार्यशाला के बारे में और ये भी बताएंगे कि यह भाजपा के लिए इतनी अहम क्यों है?

भाजपा सांसद कार्यशाला को आप पार्टी का पॉलिटिकल स्कूल कह सकते हैं। यहां सांसदों को बताया जाता है कि जनता तक कैसे पहुंचना है। कैसे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है और विपक्ष के बार का जवाब कैसे देना है। यानी इसमें कमलेश पासवान आत्मनिर्भर भारत पर, सुधांशु त्रिवेदी स्वदेशी भारत पर, बांसुरी स्वराज ईंज और डूइंग बिजनेस पर और डॉ। हेमांग जोशी ने युवा शक्ति और रोजगार पर सांसदों की बलास ली। सांसदों को समझाया गया कि सरकार की नीतियां आत्मनिर्भरता और युवाओं को जिन्हें बाद में सरकार की नीतियों में जगह मिल सकती है। आपको बतादे कि प्रधानमंत्री नंद्र मोदी हमेशा से सांसद कार्यशालाओं में हिस्सा लेते रहे हैं। लेकिन पहले वे ज्यादातर उद्घाटन या समापन भाषण देकर निकल जाते थे। इस बार का बदलाव यही है कि उन्होंने पूरे दिन इस्तेमाल कैसे करें, इसे समझाया। तो क्षेत्र की चर्चा में किसान सम्मान निधि पर बात होनी है। शहरी क्षेत्र की बात स्वच्छता अभियान पर फोकस रही तो पहाड़ी और उत्तर-पूर्व क्षेत्र का जिक्र आया तो सीमावर्ती क्षेत्र का विकास मुद्दा रहा।

बता दें कि इस दो दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य विधायी कौशल, शासन रणनीतियों और राजनीतिक संचार पर ध्यान देना है। नेताओं ने केंद्र सरकार के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने और विपक्ष का सुकाबला करने के तरीकों पर चर्चा की। रविवार को सांसद पूरे दिन की कार्यशाला में शामिल हुए। सोमवार को भी तीन घंटे का एक और सत्र निर्धारित है।

बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव 9

चेतावनी है कि यदि अब भी नहीं चेते तो भविष्य और भी विकराल होगा। महात्मा गांधी ने कहा था- ह्यकृत हर किसी की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन किसी के लालच को नहीं द्वारा यही सच्चाई है। यदि हमने संतुलन नहीं सीखा, तो यह विनाशकारी हश्य आने वाले वर्षों में और भयावह होंगे। लेकिन यदि हमने चेतावनी को अवसर माना, तो प्रकृति फिर से मां की तरह हमें संभाल लेगी। जीवनदायी पानी जब अपने विकराल रूप में सामने आता है तो उसका प्रकोप कितना घातक और विनाशकारी हो सकता है, यह इस वर्ष की मूसलधार मानसूनी बारिश एवं बादल फटने की घटनाओं ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है। सामान्यतः जल जीवन का आधार है, लेकिन जब वहाँ जल अपनी मयार्द तोड़कर प्रलयकारी रूप में आता है तो घर, खेत, सड़क, पुल, मंदिर-मस्जिद और मानवीय जीवन तक बहाकर ले जाता है। उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्य इस समय प्रकृति के ऐसे ही कहर का दंश झेल रहे हैं। बादल फटने की अप्रत्याशित घटनाएं, पहाड़ों से टूटे हिमखण्ड, अचानक बहते मलबे और बेकाबू नदियों का सेलाब-ये सब मिलकर भयावह परिवृश्य खड़ा कर रहे हैं।

वनों की कटाई ने न केवल भूमि की जलधारण क्षमता घटाई है, बल्कि स्थानीय जलवायु चक्र को भी प्रभावित किया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ा है, जिससे पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर तेजी से

प्रतीक बन गई है, जहां प्रधानमंत्री ने अपनी सादगी से सभी को प्रभावित किया। भाजपा ने उपराष्ट्रपति चुनाव की रणनीति और तैयारी के लिए दिल्ली में सांसदों की एक विशेष कार्यशाला आयोजित की थी। इस कार्यक्रम की कार्यवाही रविवार सुबह से शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें शुरूआत से ही हिस्सा लिया। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पहुंचे, तो उन्होंने आगे की सीट पर बैठने की बजाय पीछे की पक्की चुन ली। वह एक सामान्य कार्यकर्ता या सांसद की तरह क्रमांक में शामिल हुए, और जनता तक योजनाओं को कैसे पहुंचाना है और विपक्ष के नैरेटिव का जवाब कैसे देना है।

इस कार्यशाला में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद केंद्रीय मंत्री, पार्टी अध्यक्षों वाली क्लास नहीं, बल्कि चुनावी मैदान के लिए ट्रेनिंग क्लास। इसका उद्देश्य सांसदों को सरकार की नीतियों, योजनाओं और राजनीतिक रणनीतियों के साथ जोड़ना होता है। यह सांसदों के लिए सीखने, समझने और साझा करने का मंच है। यहां सांसदों को बताया जाता है कि जनता तक योजनाओं को कैसे पहुंचाना है और विपक्ष के नैरेटिव का जवाब कैसे देना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को यह दिखाया कि वह सिर्फ नेतृत्व नहीं करते, बल्कि सुनते भी हैं। यह संदेश गया कि प्रधानमंत्री सांसदों की राय सुनने आए हैं, सिर्फ भाषण देने नहीं। यह पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक संवाद को मजबूत करता है। इससे पार्टी में लोकतांत्रिक माहौल और मजबूत होता है। यह सांसदों का हर सत्र में बैठकर सांसदों की बातें सुनें। यह पार्टी कार्यकर्ताओं और सांसदों को यह संदेश देने का तरीका है कि हर आवाज मायने रखती है और जमीनी अनुभव को महत्व दिया जाता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को यह दिखाया कि वह सिर्फ नेतृत्व नहीं करते, बल्कि सुनते भी हैं। यह संदेश गया कि प्रधानमंत्री सांसदों की राय सुनने आए हैं, सिर्फ भाषण देने नहीं। यह पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक संवाद को मजबूत करता है। इससे पार्टी में लोकतांत्रिक माहौल और मजबूत होता है। यह सांसदों का संगीता यादव ने महिला समूह की सोशल मीडिया अप्रैच पर बात की। सांसदों को यह समझाया गया कि जनता तक सीधे पहुंचने का सबसे बड़ा माध्यम आज सोशल मीडिया है। हर सांसद को डिजिटल कम्युनिकेशन स्किल सीखनी होगी। तीसरा सत्रः स्थायी समितियों के सम्मेंटों की- चर्चार्सिय जायसवाल और बांसुरी स्वराज ने कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य पर बात की। तेजस्वंत पांडा और संबित पात्रा ने रक्षा, विदेश, आईटी पर। ऊर्जा, कोल, इंडस्ट्री पर शशांक त्रिपाठी और अपराजिता सारंगी ने बात रखी। सिंतंबर को होगा। प्रधानमंत्री मोदी उपराष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले, सोमवार को भाजपा और उसके सहयोगी दलों के सांसदों के लिए रात्रिभोज का आयोजन भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सीधी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड़ी के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि, संख्या बल के आधार पर राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है।

उनके प्राकृतिक प्रवाह में मानवीय हस्तक्षेप-बेतरतीब बांधा, अतिक्रमण, नालों में बदल चुकी धारा और किनारों पर बसी बस्तियाँ। भारत में हर साल ऐसतन 1,600 लोग बाढ़ से मारे जाते हैं और लगभग 75 लाख लोग प्रभावित होते हैं। फसलें तबाह होती हैं, पशुधन मरता है और अरबों रुपए की आर्थिक क्षति होती है। केवल 2023 में उत्तराखण्ड, हिमाचल और दिल्ली में आई बाढ़ से 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। पिछले कुछ दशकों में मौसम का पैटर्न पूरी तरह बिगड़ चुका है। मानसून जो पहले जून से सिंतंबर तक नियमित हुआ करता था, अब अनिश्चित और असमान हो गया है। कभी 24 घंटे में हानि जा रहा चुनाव महज जात-हर तक सीमित नहीं है। असली लड़ाई जीत के अंतर को बढ़ाने और विपक्ष की एकजुटता को कमजोर करने की है। यहीं कारण है कि सत्ता और विपक्ष, दोनों खेमों ने अपनी-अपनी रणनीतियों को आक्रामक बनाया है। एनडीए की ओर से सीधी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं और उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने कांगड़ासप्त वृष्टि पर डाल दी। बावजूद इसके, यह सवाल बना रहा कि क्या अमित शाह का यह कदम केवल शिष्टाचार था या फिर किसी गहरी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा।

राजीव राय का राजनीतिक सफर भी इस बहस को और दिलचस्प बनाता है। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने घोसी सीट से एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर को हराया और सपा के लिए बाना राधाकृष्णन का जात तथा हा। इसके विपरीत इंडिया गठबंधन के पास 324 वोट का अनुमान है। इसमें कांग्रेस के 99 लोकसभा और 26 राज्यसभा सांसद, सपा के 37, टीएमसी के 29, डीएमके के 22 और आम आदमी पार्टी के 10 सांसद शामिल हैं। हालांकि 18 सांसद ऐसे हैं, जिनका रुख अब तक साफ नहीं है। इनमें बीजेडी के 7, बीआरएस के 4,

बाईएसआरसापा ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया था। बीजेडी भी अतीत में एनडीए को समर्थन देती रही है और इस बार भी संभावना इसी की है। बीआरएस के 4 सांसद और कुछ निर्दलीय भी एनडीए के खेमे में जा सकते हैं। इन हालात में विपक्ष की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं।

दूसरी ओर इंडिया गठबंधन इस चनाव को वैचारिक लड़ाई के रूप में उसके कुछ सासदों के क्रांति वाटन करने की चाचा जोरों पर है। राजीव राय जैसे नेता, जिनका व्यवसाय भी फैला हुआ है, सत्ता पक्ष से संबंध बनाए रखना चाहते हैं। वहाँ, विपक्ष इस चुनाव को वैचारिक रंग देकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है। लेकिन अब तक के हालात बताते हैं कि विपक्ष न सिर्फ हार की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि उसकी एकजटा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

महीनों की बारिश हो जाती है, तो कभी लंबे सूखे का दौर देखने को मिलता है। 2013 की केदारनाथ त्रासदी ने पहाड़ों में अंधाधुंध निर्माण की पोल खोल दी। 2023 में दिल्ली में यमुना का 45 साल का रिकॉर्ड टूटना इस बात का संकेत है कि शहर जलवायु परिवर्तन और अत्यवर्स्थित शहरीकरण के सामने पूरी तरह असुरक्षित हो चुके हैं।

देश के लगभग हर हिस्से में जल प्रलय की कहानियाँ देखी जा सकती हैं। उत्तराखण्ड और हिमाचल में पहाड़ टूट रहे हैं, भूस्खलन से गांव उजड़ रहे हैं। बिहार और असम में बाढ़ हर साल लाखों लोगों को बेघर कर देती है। दिल्ली और मुंबई जैसे आधुनिक महानगर भी जलजमाव से पंग हो जाते हैं। राजस्थान जैसे रेगिस्तानी राज्य में भी अनियन्त्रित बारिश और बाढ़ का नया खतरा मंडरा रहा है। सड़कों पर नावें चल रही हैं, पुल बह गए हैं, खेत-खलिहान जलमग्न हैं। यह नजारा केवल विनाश का नहीं, बल्कि हमारी नासमझी का प्रमाण है। प्रकृति बार-बार संकेत देती है कि संतुलन ही जीवन का आधार है, लौकिक हमने उसकी सीमाओं को लांघ दिया है। पहाड़ों को खोखला कर सुरुरंगे और सड़कें बनाई गईं। जंगलों को काटकर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए गए। नदियों को उनके मार्ग से हटाकर कृत्रिम रास्तों में बांध दिया गया। आज जब बादल फटते हैं या नदियाँ बेकाबू होती हैं, तो यह केवल आपदा नहीं बल्कि प्रकृति का प्रतिशोध है।

अब सबल यह है कि इस संकट से निपत्ते कैसे। केवल गहर और रुचाव का गठबंधन न सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी. सुदर्शन रेड़ी को मैदान में उतारा है और चुनाव को वैचारिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पूरे माहाल में सबसे ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई फोन कॉल को लेकर है, जिसने क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं पर नई बहस छेड़ दी है। 16 सितंबर को राजीव राय का जन्मदिन था। इस मौके पर अमित शाह ने उन्हें फोन कर बधाई दी। यह कॉल सतह पर रहा है। विपक्ष छाड़ा गठबंधन ने महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। उन्हें अखिलेश यादव का करीबी और रणनीतिक माना जाता है। दिल्ली स्पष्ट यह भी है कि उनकी जीत में बीजेपी के पंपरागत वोटरों का योगदान माना गया था। ऐसे में सत्ता पक्ष से तालमेल बनाए रखना उनके लिए व्यावहारिक राजनीति हो सकती है। यही कारण है कि यूपी-बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि सपा के कुछ सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पक्ष में वोट डाल सकते हैं। बीजेपी के अपने सांसदों के लिए प्रशिक्षण सत्र कराए हैं ताकि कोई वोट इनमें बाज़ा के 7, बाजार-एस का 4, अकाली दल का 1, जेडीएस का 1, बीओटीटीपी का 1 और 3 निर्दलीय सांसद शामिल हैं।

चुनाव गुप्त मतदान और एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली से होता है। इसमें सांसदों को प्राथमिकता अंकित करनी होती है और गलत वोटिंग से मतपत्र रद्द हो सकता है। यही कारण है कि क्रॉस वोटिंग की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। इस बार भी यही स्थिति है। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए उदाहरण बताते हैं कि गुप्त मतदान में व्यक्तिगत समीकरण और सत्ता पक्ष की लॉबिंग अहम होती है। अमित शाह का राजीव राय को फोन कॉल इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

युवाओं में गहरी नाराजगी और असंतोष पैदा हुआ है। युवा पांडी पहले ही देश की कमजोर स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से तंग आ चुकी है। ऐसे समय में सोशल मीडिया पर पांडी ने उनकी निराशा को और बढ़ा लैकिन इसे कैबिनेट निर्णय के अनुरूप नियन्त्रित करना आवश्यक था, लैकिन इसे कैबिनेट निर्णय के माध्यम से लागू करना और विवादास्पद प्रावधान लागू करना— जैसे हासमर्याप्त सामग्रीह को 24 घंटे में हटाना, जैसी नीति को थोपना गलत था। पहले ही दक्षिण एशिया में लोकांत्र और पर सत्कर्त नजर रखनी चाहिए। यह सतर्कता केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें कूर्तनीतिक संवाद, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संपर्क के माध्यम से नेपाल के लोकांत्रिक ढांचे और सामाजिक संबंध गहरे हैं। ऐसे में नेपाल में बदलती

युवाओं का वयाकरण लेड़ा के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि यह सविधान और लोकांत्रिक मूल्यों की रक्षा का सवाल है। उन्होंने बी. सुदर्शन रेड़ी को इस रूप में पेश किया है कि वे सविधान की भूमिका रही। लोकसभा स्पीकर चुनाव 2019 में भी ओम बिरला को ऐसे ही अतिरिक्त वोट मिले थे। ये सभी उदाहरण बताते हैं कि गुप्त मतदान में व्यक्तिगत समीकरण और सत्ता पक्ष की लॉबिंग अहम होती है। अमित शाह का राजीव राय को फोन कॉल इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

कैबिनेट निर्णय या ताकालिक आदेश पर जोर देना चाहिए। विवादास्पद प्रावधानों की समीक्षा और विशेषज्ञ सलाह से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कानून निष्पक्ष और संतुलित हो।

इसके अलावा, युवाओं की

अब सबला यह ह कि इस सकारात्मक संनिधि को कवल राहत और मुआवजा देना समाधान नहीं है। आवश्यकता है दीर्घकालिक और ठोस कदम उठाने की। हमें ज़ंगल बचाने होंगे, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करना होगा, शहरी योजनाओं में जलनिकासी और हरियाली को महत्व देना होगा, पर्वतीय विकास में संयम लाना होगा और सबसे बढ़ावा देना होगा। इस घटनाक्रम का भारत और दक्षिण एशिया के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश है। नेपाल भारत का निकटतम पड़ोसी और गणनीय दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है। वर्ता वालों का नियन्त्रण करना होगा। इसके अलावा, योजनाओं को जलनिकासी और हरियाली के लिए विश्वास का संकेत बनाना होगा। इसके अलावा, योजनाओं को जलनिकासी और हरियाली के लिए विश्वास का संकेत बनाना होगा।

रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है। वहाँ की गलत नीतियों की आपदाएँ हैं जो समझा जाए। इसका अर्थ है कि इनका समाधान केवल राहत और बचाव सीमा सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है, बल्कि चीन जैसे बाहरी प्रभावों को बढ़ावा देने का अध्ययन और स्थानीय समुदायों के अनुभवों को मिलाकर ऐसी नीतियाँ बननी चाहिए, जो पहाड़ों की प्राकृतिक संरचना और पारिस्थितिकी को बनानी चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति हमें चेतावनी दे रही है कि यदि हमने समय रहते संतुलित विकास का मार्ग नहीं चुना तो भविष्यत में विफल रही, तो राजनीतिक समझें में विफल रही, तो राजनीतिक परादर्शिता और संवेदनशील कूटनीति की रक्षा आवश्यक है। नेपाल की सरकार को अब यह समझना होगा कि विदेशी ऐस्स को कानूनी दायरे में लाना उचित है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि वह अपनी पकड़ बनाये हुए है। ऐसे में नेपाल के लोकतात्त्विक संस्थानों में अविश्वास और अशांति बढ़ी तो यह भारत के लिए रणनीतिक चुनौती बन सकती है।

नेपाल सरकार को इस स्थिति को संभालने के लिए संतुलित और पारदर्शी और अशांति बढ़ी तो यह भारत के लिए रणनीतिक चुनौती बन सकती है।

और अधिक भयावह होगा। पूर्व चेतावनी प्रणाली को सशक्त बनाना, पहाड़ी राज्यों के बीच आपसी समन्वय बढ़ाना, आपदा प्रबंधन तंत्र को त्वरित और प्रभावी बनाना, और सबसे बढ़कर-वनों एवं प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, यह सब आज की सबसे बड़ी जरूरत है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली भारी जन-धन हानि को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस वर्ष की बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं केवल त्रासदी नहीं, बल्कि एक स्पष्ट सदैश हैं-कि प्रकृति के साथ असंतुलन की कीमत हमें अपने अस्तित्व से चुकानी पड़ सकती है। इसलिए विकास की नीतियों को पर्यावरण की दृष्टि से पुनर्परिभाषित करना ही इस देश के भविष्य के निमार्त हैं; उनकी आवाज को दबाना, उन्हें अपमानित करना और डिजिटल माध्यमों पर नियंत्रण लगाना केवल अस्थायी समाधान होगा, जबकि अस्थिरता और युवा चेतना के लिए एक गंभीर चुनौती है। फेसबूक, यूट्यूब, क्लास्सेप, इस्टाग्राम और स्पैफैट जैसे प्लेटफॉर्म्स, जिन्हें युवा पीढ़ी अपने विचार व्यक्त करने, दोस्तों से जुड़ने और वैशिक विदेशी प्रभावों के जाल में फँसता जा रहा है। यह ठीक है कि सोशल मीडिया को देश के भविष्य के निमार्त हैं; उनकी आवाज को दबाना, उन्हें अपमानित करना और डिजिटल माध्यमों पर नियंत्रण लगाना केवल अस्थायी समाधान होगा, जबकि अस्थिरता और सामाजिक तनाव स्थायी रूप से बढ़ सकते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि नेपाल अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता के बावजूद विदेशी प्रभावों के जाल में फँसता जा रहा है। यह ठीक है कि सोशल मीडिया को संवाद की आवश्यकता है। सोशल मीडिया एस पर प्रतिबंध का उद्देश्य और कानूनी आधार स्पष्ट करना जरूरी है ताकि जनता को यह विश्वास हो कि यह कदम सिर्फ़ डिजिटल सुरक्षा और कानूनी संगति के लिए उठाया गया है, न कि युवाओं की आवाज दबाने के लिए। इसके साथ ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को नियंत्रित करने के लिए एक समग्र और न्यायसंगत कानून तैयार करना चाहिए।

इस्तेमाल करती है, उन पर बैन लगाने से कानूनी और सामाजिक वास्तविकताओं राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि इसलिए भारत को नेपाल के हालात किया जाना चाहिए, न कि केवल -नीरज कुमार दुबे

नकाबपोश बदमाशों ने युवक पर की अंधाधुंध फायरिंग, हालत गंभीर

सरायखाजा थाना क्षेत्र में आए दिन हो रही घटनाओं से क्षेत्र में दहशत

जौनपुर(उत्तरशक्ति)। सरायखाजा थाना क्षेत्र के व्यक्ति से बातचीत कर रहा था। तभी मोटरसाइकिल से उड़ली गाड़ी में बीती रात करीब 8 बजे उस समय सनसनी फैल गई। जब मोटरसाइकिल पर सवार तीन नकाबपोश बदमाशोंने एक युवक पर ताबड़ोड़ फायरिंग कर दी। अधिकारी का फायदा उठाकर हमलात की मौके से फरार हो गए। गोली लगने से युवक मांगीर रूप से घायल हो गया। जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहाँ चिकित्सकोंने हालत नाजुक देखते हुए उसे वाराणसी रेफर कर दिया। उक्त गांव निवासी लालता यादव का पुत्र योगेंद्र उर्फ हसनु (40) रविवार रात घर से करीब 150 मीटर दूर सड़क किनारे रिहाया।



पहचं बदमाशोंने उस पर गोलीयां बरसाया और शैश्वरी और विभिन्न समाजों के लोग शामिल हुए। सम्मेलन में वक्ताओंने भगवान चित्रगुप्त जी को न्याय और सत्य के प्रतीक बताते हुए कहा कि वे किसी एक जाति या समाज को नहीं, बल्कि समस्त मानवता के देवता हैं।

मुख्य अधिकारी पूर्व कैविनेट मंत्री एवं प्रवागारज पश्चिम से

विद्यायक विद्यालय नाथ सिंह के लिए हुआ गया। गोली लगने से योगदान के कंधे और पेट में गंभीर चोटें आईं। गोलीयों की तड़तड़ाट से गांव में दहशत फैल गई। परिजनोंने तकालुक पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को खुलेंस से जिल अस्पताल भिजवाया। उधर, घटनास्थल की तलाश में भर्ती कराया गया। जहाँ चिकित्सकोंने हालत नाजुक देखते हुए उसे वाराणसी रेफर कर दिया। उक्त गांव निवासी लालता यादव का पुत्र योगेंद्र उर्फ हसनु (40) रविवार रात घर से करीब 150 मीटर दूर सड़क किनारे रिहाया।

तलाशी के दौरान पुलिस को एक खोखा भी बरामद हुआ। थाना प्रभारी ने बताया कि घायल का इलाज चल रहा है और मामले की गहन जांच की जा रही है। बदमाशों की तलाश में पुलिस सक्रिय है।

व्यापारी से जमीन हड्डपने के मामले में सीजेएम कोर्ट में पेश हुए अब्बास अंसारी

गांधीपुर(उत्तरशक्ति)। व्यापारी की जमीन जबरन हड्डपने के मामले में अब्बास अंसारी आज सीजेएम कोर्ट में पेश हुए। वह मामला 2023 में दर्ज हुआ था। एक व्यापारी नेता ने सदर कोतवाली में अब्बास अंसारी के खिलाफ शिकायत दर्ज की रही है।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अंसारी ने जबरन उनकी जमीन हड्ड पली। इस मामले में कोर्ट ने अब्बास अंसारी को तलब किया गया। आज अब्बास सीजेएम कोर्ट को बाद अगली तारीख 24 सितंबर तक यह की गई है।

वर्ष 2012 में मुख्यार्थी

व्यापारी नेता अबु फखर से जमीन खरीदने का दावा किया था। जबकि वर्ष 2023 में व्यापारी नेता अबु फखर ने मुख्यार्थी अंसारी लखनऊ जेल में बंद था। उस समय मुख्यार्थी ने मझे लखनऊ जेल बुलाया था और मेरी रौजा स्थित जमीन को अपने परिजनों के नाम रजिस्टरी करने के लिये धमकाया। मैंने डॉ के मारे जमीन को अब्बास अंसारी के अंसारी आफिक रजा, अनवर शहजादी और अरोपी हैं।

मालूम होगी जहाँ एक तरफ मुख्यार्थी अंसारी की मौत हो चुकी है वहाँ दूसरी तरफ वादी अबु फखर खान की भी मौत हो चुकी है। बता दें यामल जमीन की जबरदस्ती कराने से में पेश हुए। यामल की बाद अब्बास कोतवाली में एक बाद अगली तारीख 24 सितंबर तक बाद अगली तारीख 24

सितंबर तक यह की गई है।

वर्ष 2012 में मुख्यार्थी

ने अबु फखर से

जिसके सन्दर्भ में वादी ने सिंगरा

को बाद अगली तारीख 24

सितंबर तक यह की गई है।

वर्ष 2012 में मुख्यार्थी

ने अबु फखर से

जिसके सन्दर्भ में वादी ने सिंगरा

को बाद अगली तारीख 24

सितंबर तक यह की गई है।

वर्ष 2012 में मुख्यार्थी

ने अबु फखर से

जिसके सन्दर्भ में वादी ने सिंगरा

को बाद अगली तारीख 24

सितंबर तक यह की गई है।

वर्ष 2012 में मुख्यार्थी

ने अबु फखर से

जिसके सन्दर्भ में वादी ने सिंगरा

को बाद अगली तारीख 24

सितंबर तक यह की गई है।

वर्ष 2012 में मुख्यार्थी

ने अबु फखर से

जिसके सन्दर्भ में वादी ने सिंगरा

को बाद अगली तारीख 24

सितंबर तक यह की गई है।

वर्ष 2012 में मुख्यार्थी

ने अबु फखर से

जिसके सन्दर्भ में वादी ने सिंगरा

को बाद अगली तारीख 24

सितंबर तक यह की गई है।

वर्ष 2012 में मुख्यार्थी

ने अबु फखर से

जिसके सन्दर्भ में वादी ने सिंगरा

को बाद अगली तारीख 24

सितंबर तक यह की गई है।

वर्ष 2012 में मुख्यार्थी

ने अबु फखर से

जिसके सन्दर्भ में वादी ने सिंगरा

को बाद अगली तारीख 24

सितंबर तक यह की गई है।

वर्ष 2012 में मुख्यार्थी

ने अबु फखर से

जिसके सन्दर्भ में वादी ने सिंगरा

को बाद अगली तारीख 24

सितंबर तक यह की गई है।

वर्ष 2012 में मुख्यार्थी

ने अबु फखर से

जिसके सन्दर्भ में वादी ने सिंगरा

को बाद अगली तारीख 24

सितंबर तक यह की गई है।

वर्ष 2012 में मुख्यार्थी

ने अबु फखर से

जिसके सन्दर्भ में वादी ने सिंगरा

को बाद अगली तारीख 24

सितंबर तक यह की गई है।

वर्ष 2012 में मुख्यार्थी

ने अबु फखर से

जिसके सन्दर्भ में वादी ने सिंगरा

को बाद अगली तारीख 24

सितंबर तक यह की गई है।

वर्ष 2012 में मुख्यार्थी

ने अबु फखर से

जिसके सन्दर्भ में वादी ने सिंगरा

को बाद अगली तारीख 24

सितंबर तक यह की गई है।

वर्ष 2012 में मुख्यार्थी

ने अबु फखर से

जिसके सन्दर्भ में वादी ने सिंगरा

को बाद अगली तारीख 24

सितंबर तक यह की गई है।

वर्ष 2012 में मुख्यार्थी

ने अबु फखर से

जिसके सन्दर्भ में वादी ने सिंगरा

को बाद अगली तारीख 24

सितंबर तक यह की गई है।

वर्ष 2012 में मुख्यार्थी

ने अबु फखर से

जिसके सन्दर्भ में वादी ने सिंगरा

को बाद अगली तारीख 24

सितंबर तक यह की गई है।

वर्ष 2012 में मुख्यार्थी

ने अबु फखर से

जिसके सन्दर्भ में



मीरा-भायंदर में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन के लिए कमिशनर के साथ मंत्री सरनाईक की बैठक संपन्न

सिवान (उत्तरशक्ति) | बिहार के सिवान जिला अंतर्गत महाराजगंज स्थानीय शहर के गोरख सिंह विहारियालय के बीच पट्टी प्रभाग में सोनमारा को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के निदेशक सह अध्यक्ष डॉ अर्चन कुमार सिंह ने कहा कि इस दिवस पर हम प्रति वर्ष की भाविता शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। जो एक मौलिक अधिकार है और सतत विकास पैदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मीरा-भायंदर महानगरपालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। उमुख्यमंत्री एकाधिकारी से मुख्यमंत्री कार्यकाल में, मंत्री सरनाईक के प्रयासों से, सरकार ने मीरा-भायंदर के लिए विभिन्न विकास कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

महानगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिया है। नगर निगम चूनाव की घोषणा जल्द ही हो जाएगी। आचार संहिता लागू होने से पहले सभी चालू कार्यों को पूरा करने पर ध्यान जल्द ही दिए जाएं। हम इमेजन, डीएल, सामुदायिक बवन, साइकिल ट्रैक, जार्जिंग ट्रैक जैसे सभी विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि शहर के नागरिकों को अच्छी सुविधाएँ मिल सकें। एमएमआरडीए, नगर निगम और संबंधित विभाग समय पर काम पूरा करें और तकनीकी के बारे में बात करते हुए, मंत्री सरनाईक ने कहा कि हैंदू हृदय कर्मीने पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उपस्थिति के सफल आयोजन हेतु महाविद्यालय के समर्पणपत्रों एवं प्रशिक्षुओं को ध्वन्यावाद ज्ञापित किया।

</

